



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 2005/वैशाख 10, 1927

No. 178]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 2005/VAISAKHA 10, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 254(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"सं.आ. 208"

महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व)

संशोधन आदेश, 2005

राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) आदेश, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रभावी करते हुए किया है;

और उक्त आदेश 1 मई, 1994 से प्रवृत्त हुआ तथा उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के निबंधनों के अनुसार इसे 30 अप्रैल, 1999 तक या उस तारीख तक, जो राष्ट्रपति इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, प्रवृत्त रहना था;

और उक्त आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की स्थापना उक्त आदेश के प्रवृत्त रहने, अर्थात् 30 अप्रैल, 1999, तक के लिए थी;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 175 में यह विनिर्दिष्ट किया था कि महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 1999, 30 अप्रैल, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 1999 के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि को 30 अप्रैल, 2004 तक बढ़ा दिया था;

और राष्ट्रपति ने उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान आदेश 203 में यह विनिर्दिष्ट किया था कि महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 2004, 30 अप्रैल, 2005 तक प्रवृत्त रहेगा;

और महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) संशोधन आदेश, 2004 के अनुसरण में, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की अवधि को 30 अप्रैल, 2005 तक बढ़ा दिया था;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उक्त विकास बोर्डों को उक्त क्षेत्रों के हित में बनाए रखना समीचीन समझा है और महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति से उक्त आदेश की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः, अब, राष्ट्रपति, उक्त आदेश के खंड 1 के उपखंड (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 2006 तक प्रवृत्त रहेगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19 (7)/2005-वि. 1]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2005

G.S.R. 254(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O. 208”

THE STATE OF MAHARASHTRA (SPECIAL RESPONSIBILITY OF GOVERNOR FOR VIDARBHA, MARATHWADA AND THE REST OF MAHARASHTRA) AMENDMENT ORDER, 2005

WHEREAS the President has, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, made the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994 (hereinafter referred to as the said Order) giving effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra by the Governor of that State;

AND WHEREAS the said Order came into force with effect from the 1st day of May, 1994 and in terms of sub-clause (3) of clause 1 of the said Order it was to remain in force up to the 30th day of April, 1999 or up to such date as the President may, by order made in this behalf, specify;

AND WHEREAS in pursuance of the said Order, the Governor of Maharashtra had set up the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra till the said Order remained in force, that is, up to the 30th day of April, 1999;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 175 that the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999 shall remain in force up to the 30th day of April, 2004;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 1999, the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2004;

AND WHEREAS the President, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution, read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, had specified in the Constitution Order 203 that the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004 shall remain in force up to the 30th day of April, 2005;

AND WHEREAS in pursuance of the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Amendment Order, 2004, of the Governor of Maharashtra had extended the term of the Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra up to the 30th day of April, 2005;

AND WHEREAS the Governor of Maharashtra considers it expedient in the interest of the said areas to continue the said Development Boards and on the approval of the State Government of Maharashtra has requested the President to extend the duration of the said Order;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 371 of the Constitution read with sub-clause (3) of clause 1 of the said Order, the President hereby specifies that the said Order shall remain in force up to the 30th day of April, 2006.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President

[F. No. 19(7)/2005-L.1]
T. K. VISWANATHAN, Secy.